



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21062023-246727
CG-DL-E-21062023-246727

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430]
No. 430]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 21, 2023/ज्येष्ठ 31, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 21, 2023/JYAISHTHA 31, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 जून, 2023

फा. सं. बीएस /11/11/2023.—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 12 और धारा 13 के साथ पठित धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्यूरो, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) संशोधन विनियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त विनियम कहा गया है) में, अनुसूची-II में, स्कीम -II में, पैरा 5 में, उप-पैरा (6) के स्थान पर, -
(क) निम्नलिखित उप-पैरा में रखा जाएगा, जो तारीख 1 जून, 2023 से प्रभावी होगा अर्थात्:-

"(6) सूक्ष्म उद्यमों पर प्रक्रिया फीस में अस्सी प्रतिशत और लघु एवं मध्यम उद्यमों पर बीस प्रतिशत की रियायत लागू होगी;"

(ख) तारीख 01 जून, 2026 से निम्नलिखित उप-पैरा में रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(6) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रक्रिया फीस में बीस प्रतिशत की रियायत लागू होगी।"

3. उक्त विनियमों की अनुसूची-II के स्कीम-IV में, पैरा 5 के उप-पैरा (2) में, परन्तु के स्थान पर, -

(क) निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, जो तारीख 01 जून, 2023 से प्रभावी होगा अर्थात्: -

"परन्तु सूक्ष्म उद्यमों को अस्सी प्रतिशत और लघु एवं मध्यम उद्यमों को बीस प्रतिशत की रियायत दी जाएगी;"

(ख) निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, जो तारीख 01 जून, 2026 से प्रभावी होगा अर्थात्: -

"परन्तु कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को बीस प्रतिशत की रियायत दी जाएगी।"

अलका, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./211/2023-24]

टिपण्ण : मूल विनियम फा.सं. बीएस/11/11/2018 तारीख 4 जून 2018 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित किया गया और फा.सं. बीएस 11/11/2018 तारीख 12 अक्टूबर, 2018, फा.सं. बीएस/11/11/2020 तारीख 21 फरवरी, 2020, फा.सं. बीएस/11/11/2021 तारीख 4 फरवरी, 2021, फा.सं. बीएस/11/11/2021 तारीख 5 फरवरी, 2021, फा.सं. बीएस/11/11/2021 तारीख 4 जून, 2021, फा.सं. बीएस/11/11/2021 तारीख 5 अगस्त, 2021, फा.सं. बीएस/11/11/2021 तारीख 27 अक्टूबर, 2021, फा.सं. बीएस/11/11/2021 तारीख 8 दिसंबर, 2021 और एफ.सं. बीएस/11/11/2021 तारीख 16 मार्च, 2022 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2023

F. No. BS/11/11/2023 - In exercise of the powers conferred by section 39 read with sections 12 and 13 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Bureau, with prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Amendment Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018 (hereinafter referred to as the said regulations), in Schedule -II, in Scheme-II, in paragraph 5, for sub-paragraph (6), -

(a) with effect from 1st day of June, 2023, the following sub-paragraph shall be substituted, namely :-

“(6) Concession in processing fee of eighty per cent shall be applicable to micro enterprises and twenty percent shall be applicable to small and medium enterprises;”;

(b) with effect from 1st June, 2026, the following sub-paragraph shall be substituted, namely: -

“(6) Concession in processing fee of twenty per cent shall be applicable to micro small and medium enterprises”.

3. In the said regulations, in Schedule-II, in Scheme –IV, in paragraph 5, in sub-paragraph (2), for the proviso, -

(a) with effect from 1st day of June, 2023, the following proviso shall be substituted namely:-

“Provided that a concession of eighty per cent shall be given to micro enterprises and twenty per cent to small and medium enterprises;”;

(b) with effect from 1st June, 2026, the following proviso shall be substituted, namely: -

“Provided that a concession of twenty per cent shall be given to micro small and medium enterprises”.

ALKA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./211/2023-24]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* F.No. BS/11/11/2018 dated the 4th June, 2018 and subsequently amended *vide* F.No. BS/11/11/2018 dated the 12th October, 2018, F.No. BS/11/11/2020 dated the 21st February, 2020, F.No. BS/11/11/2021 dated the 4th February, 2021, F.No. BS/11/11/2021 dated the 5th February, 2021, F.No. BS/11/11/2021 dated 4th June, 2021, F.No. BS/11/11/2021 dated the 5th August, 2021, F.No. BS/11/11/2021 dated the 27th October, 2021, F.No. BS/11/11/2021 dated the 8th December, 2021 and F.No. BS/11/11/2021 dated the 16th March, 2022.